VISION IAS

www.visionias.in

VISION IAS
M N 09 SEP 2022 No.
RECEIVE

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1836)

Name of Candidate	Rameer Singh		
Medium Eng./Hindi	hindi	Registration Number	319209
Center	MN	Date	3 Sep 22

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
   इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

1. The PM-AASHA scheme is aimed at improving procurement mechanism as well as ensuring remunerative prices for farmers. In this context, highlight the various components of the scheme and discuss the concerns associated with it. **(150 words) 10**

पीएम-आशा योजना का उद्देश्य खरीद तंत्र में सुधार के साथ-साथ किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। इस संदर्भ में, योजना के विभिन्न घटकों को रेखांकित कीजिए तथा इससे जुड़ी चिंताओं पर चर्चा कीजिए।

पीएम-आशा योजना MSP तंत्र की प्रभाविकता में वृद्धि करने के लिए व किसानों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए शुरु की गयी थी।

PM-AASHA योजना के घटक

① PSS (मूल्य समर्थन सेवा)

→ इसके तहत FCI, NAFED जैसी केंद्रीय एजेंसियाँ अनाज, तिलहन, कोपरा आदि की MSP पर भौतिक खरीद करेंगी।

② मूल्य अन्तर भुगतान योजना (PDPS)

→ किसान उत्पादों को निजी बाजार में विक्रय करें।

- सरकार द्वारा MSP व निजी बाजार मूल्य का अन्तर का भुगतान किया जाएगा।
  → भुगतान MSP के 25% से ज्यादा नहीं होगा।

④ निजी खरीद व स्टॉकिस्ट योजना
→ इसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित निजी इकाईयाँ दालों व तिलहन की खरीद करेगी।

PM-AASHA से जुड़ी चिंताएँ -
① निजी व्यापारियों द्वारा कार्टेलाइजेशन द्वारा भुगतान को MSP से नीचे रखना (MP की भावान्तर भुगतान योजना में देखा गया)
② PPSS में राज्यों द्वारा निजी इकाइयों की पहचान में देरी।
③ FCI व NAFED द्वारा खाद्यान्न केंद्रित खरीद (खाद्यान्न का >50% बाजार सरप्लस की खरीद, दालों की <6%, तिलहन <0.5%)

किसानों में जागरूकता वृद्धि व FCI व NAFED की भंडारण क्षमता को सार्थक व निजी व्यापार संबंधी सूचना प्रबंधन द्वारा PM AASHA को प्रभावित बनाया जा सकता है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. Explaining the concept of blended finance, discuss the role it can play in mobilizing capital for infrastructure development in developing countries like India.

(150 words) 10

मिश्रित वित्त की अवधारणा की व्याख्या करते हुए, भारत जैसे विकासशील देशों में अवसंरचना विकास हेतु पूंजी जुटाने में इसकी भूमिका पर चर्चा कीजिए।

अवसंरचना विकास में मिश्रित पूंजी से तात्पर्य सरकारी व निजी क्षेत्र की सहभागिता से है।

भारत जैसे विकासशील देशों में अवसंरचना विकास हेतु पूंजी जुटाने में मिश्रित वित्त की भूमिका -

(1) सरकार की राजकोषीय क्षमता सीमित है (2.6% of GDP - पूंजी निवेश) व अवसंरचना विकास हेतु 6 bn $ निवेश की आवश्यकता।

(2) निजी क्षेत्र की सहभागिता (जो कि NIIF, NIP आदि के माध्यम से) वित्त की कमी को पूरा कर अवसंरचना विकास को तीव्र करती है।

(3) PPP मॉडल के माध्यम से अवसंरचना विकास।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(4) NHAI जैसी संस्थाओं द्वारा ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से पूंजी जुटाना।

→ इसके निजी क्षेत्र की जोखिम व सरकारी क्षेत्र की जोखिम का समायोजन होता है।

भारत सरकार ने विभिन्न उपायों से द्वारा निजी क्षेत्र को अवसंरचना के निवेश हेतु प्रोत्साहित किया है। NIP में निजी क्षेत्र की भूमिका 22% है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. Discuss the challenges faced in the revival and revamp of dry ports in India and state the measures that can be adopted in this regard.

(150 words) 10

भारत में शुष्क पत्तनों (ड्राई पोर्ट्स) के पुनरुद्धार और सुधार में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए तथा इस संबंध में अपनाए जाने वाले उपायों का सुझाव दीजिए।

शुष्क पतन, मुख्य पतनों को सहायता प्रदान करने के लिए आंतरिक भाग में स्थित होते है।

शुष्क पतनों की भूमिका
- अस्थायी भंडारण व्यवस्था
- आंतरिक भागों तक पहुंच
- गुणवता परीक्षण, टेस्टिंग वजन आदि सहायक सुविधाएँ

शुष्क पतनों के सुधार व पुनरुद्धार में आने वाली चुनौतियां

1. सार्वजनिक क्षेत्र की मोनोपॉली
   - > 70% CONCOR द्वारा
2. बेहतर अवसंरचनात्मक विकास हेतु वित का अभाव
3. मल्टी मॉडल परिवहन के समन्वय में चुनौती
4. गुणवता परीक्षण अवसंरचना का अभाव

(5) तकनीक (बिग डेटा एनालिटिक्स, AI, RS, ब्लॉकचेन) आदि के अंगीकरण का अभाव

(6) प्रशिक्षित व समर्पित कार्यबल का अभाव

(7) महापतन पोर्ट ट्रस्ट, 1963 में चुनौतियाँ जो ड्राई पोर्ट पर के व्यापारिक एकीकरण में बाधक

अपनाये जा सकने वाले उपाय

(1) निजी क्षेत्र के लिए लेवल प्लेयिंग फील्ड का प्रावधान करना

(2) स्किल इंडिया के माध्यम से प्रशिक्षित मानव बलों का विकास

(3) भंडारण, टेस्टिंग, परिवहन आदि अवसंरचना का विकास करना।

(4) तकनीक का प्रभावी अंगीकरण करना
↳ सिंगल विंडो क्लीयरेंस,
↳ टर्न अराउंड समय को कम करना

इस प्रकार ड्राई पोर्ट में सुधार न केवल निर्यात वृद्धि में सहायक होगी बल्कि आंतरिक क्षेत्रों के विकास को भी सुनिश्चित करेगी।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. Monoculture is one of the major threats to ensuring food security and sustainability of Indian agriculture. Discuss. (150 words) 10

एकल कृषि (मोनोकल्चर) खाद्य सुरक्षा और भारतीय कृषि की संधारणीयता सुनिश्चित करने के समक्ष विद्यमान प्रमुख खतरों में से एक है। चर्चा कीजिए।

एकल कृषि से तात्पर्य व्यापक कृषि क्षेत्रों में एक ही प्रकार की फसल का उत्पादन करना।

उदा. - बड़े भू-भाग पर व्यापारिक फसलों का अबाध उत्पादन

एकल कृषि - खाद्य सुरक्षा के समक्ष खतरा

(1) पोषक पदार्थों का अभाव
- एकल कृषि विविध प्रकार के पोषकीय खाद्यान्नों का अभाव कर सकती है
(उदा) बड़े पैमाने पर गेहूं की खेती बाजरे से प्राप्त ~~~~ सूक्ष्मपोषक पदार्थों का अभाव कर सकती है

(2) खनिज संसाधनों का अत्यधिक दोहन भविष्य में खाद्यान्न उत्पादकता में कमी कर सकता है (उदा) PN व HR में कृषि उत्पादकता में कमी

(3) व्यावसायिक फसलों जैसे- कपास, तम्बाकू आदि का उत्पादन ~~न केवल~~
└ खाद्यान्न की कमी

↳ पशु चारे का अभाव → डेयरी पदार्थों की कमी।

कृषि संधारणीयता सुनिश्चित करने के समक्ष खतरा।

① भू-संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन
↳ एक ही प्रकार की फसल कुछ निश्चित संसाधनों के अतिदोहन को प्रेरित करती है।
(eg) पंजाब व HR में भूजल दोहन 100% से भी अधिक है।

② मृदा में पोषक तत्वों का असंतुलन
↳ प्राकृतिक तत्वों के साथ-साथ N:P:K अनुपात असंतुलन [वर्तमान में NP:K 8:3:1 है]

③ खाद्य शृंखला व जैव विविधता का बिगाड़
↳ परागण आदि की कमी जैव विविधता को नुकसान पहुंचाती है और भविष्य में उत्पादकता को कम करेगी।

अतः मिश्रित कृषि, परम्परागत कृषि, स्मार्ट कृषि जैसी कृषि-शस्य प्रणालियों का उपयोग करना चाहिए ताकि पर्यावरणीय स्थिरनीयता व खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. While highlighting the impact of single-use plastic on health and the environment, state the recent efforts taken by the government to curb plastic pollution in India. **(150 words) 10**

स्वास्थ्य और पर्यावरण पर एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक के प्रभाव को रेखांकित करते हुए, भारत में प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए।

भारत प्रतिवर्ष 9.46 m टन प्लास्टिक अपशिष्ट का उत्पादन करता है जिसमें से 43% एकल-उपयोग प्लास्टिक है।

एकल उपयोग प्लास्टिक का पर्यावरण पर प्रभाव

① महासागरीय पारितंत्र पर प्रभाव
→ महासागरों में GPGP (ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच) आदि के द्वारा व्यापक प्रदूषण
→ मछलियों में प्लास्टिक की मात्रा का पाया जाने के प्रमाण

② भूमि की उर्वरकता पर नकारात्मक प्रभाव
③ भूमि भराव से लीचिंग द्वारा भू-जल प्रदूषण
④ जैव विविधता पर प्रभाव – प्लास्टिक का विघटन लम्बे समय तक संभव नहीं
→ जैव आवर्धन व संचयन द्वारा खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव

स्वास्थ्य पर S-U-P का प्रभाव →

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

① प्लास्टिक दहन से निकलने वाली व भूमि भराव से जल-वायु प्रदूषण (दिल्ली के खोखला आदि)

② जैव संचयन व आवर्धन द्वारा खाद्य श्रृंखला में प्रवेश

③ अस्वच्छ वायु से असामयिक मृत्यु आदि।

प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

① प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने से संबंधित दिशा निर्देश -2016 व तत्पश्चात संशोधन
→ 1 जुलाई, 2022 से SUP पर प्रतिबंध
→ प्लास्टिक थैलियों की मोटाई में 75 माइक्रोन तक वृद्धि
→ EPR का ब्रांडमालिकों व आयातकों का प्रसार

② चक्रीय अर्थव्यवस्था हेतु WWF के साथ प्लास्टिक समझौता

③ Waste से ऊर्जा,

④ हॉट मिक्स प्लांट की सहायता से PMGSY में उपयोग

⑤ LiFE (संधारणीय जीवन शैली) को प्रोत्साहन

जागरूकता अभियान व जनभागीदारी इससे भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. Aapda Mitra – a force of volunteers from across India trained in disaster response – is becoming a game changer in the field of disaster management in the country. Elaborate. **(150 words) 10**

आपदा मित्र-आपदा प्रतिक्रिया हेतु प्रशिक्षित भारत भर के स्वयंसेवकों का एक बल-देश में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक गेम चेंजर के रूप में उभर रहा है। सविस्तार वर्णन कीजिए।

आपदा मित्र योजना NDMA द्वारा संचालित एक अभियान है, जो जन सहभागिता द्वारा आपदा प्रबंधन को बढ़ावा देता है।

आपदा मित्र- आपदा प्रतिक्रिया हेतु प्रशिक्षित स्वयं सेवकों का समूह है।

आपदा मित्र निम्नलिखित प्रकार से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में गेम चेंजर के रूप में उभर रहा है-

① राहत कार्यों में

- राहत हेतु आपदा पश्चात सहायता अनुमान लगाने व आकलन करने में सहायक
- 80% आपदा राहत कार्य स्थानीय समुदायों द्वारा किया

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

जाता है।

(2) सामुदायिक संवेदनशीलता द्वारा समुदायों की सुभेद्यता का आकलन करने में

(3) आपातकालीन सूचना प्रसार द्वारा।

(4) सरकारी व पेशेवर एजेंसियों के सहयोगी के रूप में।

(5) कुप्रबंधाली व पुनर्वास अभियानों में अग्रसक्रियता

(6) सरकारी कार्यक्रमों की प्रभाविकता व पहुंच में सुधार द्वारा।

आपदा मित्रों को ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए और उपाय किए जा सकते हैं

↳ फायर फाईटिंग उपकरण प्रदान कर

↳ निरन्तर मॉक ड्रिल द्वारा

↳ NIDM जैसी समर्पित संस्थानों द्वारा अभ्यासों के संचालन में

इस प्रकार आपदा मित्र आपदा प्रबंधन को बॉटम-अप रूप प्रदान करता है जो सेंडई फ्रेमवर्क की अवधारणा के अनुरूप है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. Why is the rise in lone wolf attacks considered as a serious challenge for security agencies around the world? Highlight the role of the internet in exacerbating such attacks. (150 words) 10

विश्व भर में लोन वुल्फ हमलों में वृद्धि को सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक गंभीर चुनौती क्यों माना जाता है? ऐसे हमलों की वृद्धि में इंटरनेट की भूमिका पर प्रकाश डालिए।

वर्तमान में आतंकवाद के भयावह रूप में लॉन वुल्फ हमले गंभीर सुरक्षात्मक चुनौती उत्पन्न कर रहे है।
(उदा) - ब्रिटेन में इकके कुचलने, न्यूजीलैण्ड में क्राइस्टचर्च की घटनाएँ

लोन वुल्फ हमलों में वृद्धि सुरक्षा एजेंसियों के लिए निम्न प्रकार से प्रमुख चुनौती है-

① आसूचना एकत्रण में समस्याएँ
- प्रभावी नेटवर्क का अभाव के कारण

② शहरी क्षेत्रों में आतंकवादी घटनाओं का सामना करने में कम प्रशिक्षण
- लोन वुल्फ अटैक ज्यादा भीड़ वाले शहरी क्षेत्रों को निशाना बनाते है

③ तकनीक का अप्रभावी उपयोग
→ सामाजिक तनाव व सोशल मीडिया के संबंधों की कम जानकारी

(4) प्रभावी समन्वय का अभाव
→ आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों - साइबर सुरक्षा तंत्र आदि के मध्य समन्वय

(5) मानसिक रोगी की घटनाएं → >40%
लोन वुल्फ अटैक मानसिक रोगियों द्वारा।

लोन वुल्फ हमलों में इंटरनेट की भूमिका
(1) इंटरनेट पर फेक न्यूज व हेट स्पीच का तीव्र प्रसार
(2) धार्मिक कट्टरवाद व आतंकी संगठनों की गतिविधियाँ
(3) सामाजिक अशांति में सर्च किए जाने कंटेंट को एल्गोरिथम द्वारा स्वत: फीचर करना।
(4) इंटरनेट पर निगरानी का अभाव
(5) OGWs में इंटरनेट की प्रभावी भूमिका
(6) क्राइस्टचर्च (न्यूजीलैण्ड) की घटना का इंटरनेट पर लाइव प्रसार → भय का तीव्र प्रसार

उपाय
→ NCCC जैसे साइबर समन्वयक की स्थापना
→ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (eg) क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन
→ सामाजिक-आर्थिक विकास
→ सोशल मीडिया पर निगरानी, AI जैसी तकनीक का उपयोग आदि।
→ शहरी क्षेत्रों के सौन्दर्यीकरण आदि।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. The fundamental inefficiencies embedded in our military structures and processes are now being addressed through a slew of defence reforms in the country. Discuss. (150 words) 10

हमारे सैन्य ढांचे और प्रक्रियाओं में अंतर्निहित मूलभूत अक्षमताओं को अब देश में विभिन्न रक्षा सुधारों के माध्यम से दूर किया जा रहा है। चर्चा कीजिए।

बदलती युद्ध परिस्थितियों व सुरक्षा परिदृश्यों ने परम्परागत सैन्य ढाँचे की गतिशीलता राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करती है।

सरकार द्वारा सैन्य ढाँचे व प्रक्रियाओं को सुधारने के लिए निम्न प्रयास किए जा रहे हैं-

① CDS के पद का सृजन
- कारगिल रिव्यू समिति ने तीनों सेना के एकीकरण व तीव्र संचालन के लिए इसकी अनुशंसा की थी।

② एकीकृत बैटल ग्रुप का प्रस्ताव
- इनमें 3T (टैंक, टाइम आदि) के आधार पर नियुक्ति

③ अग्निवीर योजना

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(4) उद्यम क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को प्रोत्साहन।

(5) रक्षा खरीद प्रक्रिया में सुधार

↳ आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन

↳ OFB का निगमीकरण

↳ आयात को कम करने हेतु विभिन्न मदों का आयात प्रतिबंध

(6) रक्षा आधुनिकीकरण हेतु नॉन-लैप्सेबल फंड का निर्माण

विभिन्न सुधारों के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देने व सेनाओं की गतिशीलता में वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. In light of the recent establishment of the WHO Global Centre for Traditional Medicine in India, discuss the advantages and challenges in mainstreaming traditional medicine in the country. **(150 words) 10**

हाल ही में, भारत में डब्ल्यू. एच. ओ. ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना के आलोक में, देश में पारंपरिक चिकित्सा को मुख्यधारा में लाने के लाभों और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।

गुजरात में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की गयी। इसने पारंपरिक चिकित्सा को पुनः मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया है।

पारंपरिक चिकित्सा को मुख्यधारा में लाने के प्रयास के लाभ

① स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता
- WHO द्वारा प्रति लाख 1000 चिकित्सक अनुशंसित है लेकिन भारत में 1:1456 है
- आयुष चिकित्सकों को शामिल करने पर 1:800 अनुपात हो जाएगा।

② दूर-दराज लोगों व जनजातियों को स्वास्थ्य लाभ
- ग्रामीण क्षेत्र जनजातियों में आयुष की स्वीकार्यता

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(3) हेल्थ को मानसिक-शारीरिक एकीकरण के रूप में मानकर स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा → 'योग' आदि के द्वारा गैर संक्रामक रोगों में कमी -
↳ भारत में ≥50% मृत्यु NCD से होती।

(4) भारतीय स्वदेशी ज्ञान का प्रसार
(5) अनुसंधान व शोध द्वारा आयुष की स्वीकार्यता व प्रभाविकता में वृद्धि
→ OOPE में कमी हो सकती है।

चुनौतियाँ

(1) न्यूनतम शोध व अनुसंधान
(2) मानकीकरण का अभाव स्वीकार्यता को कम करता है।
(3) <1% लोग अस्पतालों में भर्ती होकर आयुष पद्धति से इलाज करवाना चाहते हैं।
(4) कम वित्तीय आवंटन

किए जाने वाले उपाय → (1) आयुष मंत्रालय के बजट में वृद्धि करना
GCTM के सहयोग से मानकीकरण को प्राथमिकता प्रदान करना

भारत ने आयुष मंत्रालय द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से एकीकृत प्रणाली को तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है जो SDG-3 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. Nano Urea Liquid has the potential to transform farming in India and across the world by improving productivity while reducing environmental pollution and input cost. Discuss. **(150 words) 10**

नैनो यूरिया लिक्विड में पर्यावरण प्रदूषण और इनपुट लागत को कम करने के साथ-साथ उत्पादकता में सुधार करके भारत और विश्व भर में कृषि कार्य को रूपांतरित करने की क्षमता है। चर्चा कीजिए।

IFFCO द्वारा निर्मित नैनो यूरिया लिक्विड अपनी संधारणीयता व प्रभावकारिता के कारण व्यापक स्तर पर कृषि को रूपांतरित करने की क्षमता रखती है।

पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में सहायक

① नैनो यूरिया को प्रत्यक्षतः पौधों की पत्तों में अंतरण किया जाता है।

② इससे भूमि व जल संदूषण कम होता है।

③ इनपुट लागत को कम करने की क्षमता

① 500ml नैनो यूरिया का (240 Rs) मूल्य 1 बोरी यूरिया से कम है जबकि दोनों की प्रभाविता बराबर है।

② इससे 50% तक यूरिया उपयोग में कमी आयेगी।

④ यूरिया का आयात (जो अभी भारत में

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Gmt प्रतिबंधित) में कमी आयेगी
→ यूरिया सब्सिडी कम

उत्पादकता में सुधार

→ भूमि व जल संसाधनों की गुणवत्ता में कमी न होने पर उत्पादकता में वृद्धि

→ कम इनपुट लागत के कारण आउटपुट में सुधार

→ सब्सिडी पर कम खर्च कृषि के कैपिटल खर्च में वृद्धि होगा।

→ तकनीक के उपयोग को प्रोत्साहन - उत्पादकता में वृद्धि

इस प्रकार नैनो यूरिया वैश्विक कृषि अ-व्यवस्था को आगत गहन से संधारणीय व उत्पादक बनाएगी। जिससे खाद्य सुरक्षा व पर्यावरणीय संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।

11. Discuss the domino effect of high crude oil prices on the Indian economy. Also, enumerate the measures that India can take in this context.
(250 words) 15

भारतीय अर्थव्यवस्था पर कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के डोमिनो प्रभाव की विवेचना कीजिए। साथ ही, भारत द्वारा इस संदर्भ में अपनाए जा सकने वाले उपायों को सूचीबद्ध कीजिए।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $100 प्रति बैरल से उच्च कच्चे तेल की कीमत भारतीय ~~अर्थवत~~ अर्थव्यवस्था को व्यापक रूप से प्रभावित करती है।

भारत पर कच्चे तेल की ऊंची कीमतों का डोमिनो प्रभाव

→ भारत ऊर्जा (कच्चे तेल) का 87.2% आयात पर निर्भर है।

↓

उच्च आयात मूल्य से चालू खाता घाटे (CAD) में वृद्धि
(वर्तमान में CAD 2.7% of GDP है)

↓

① (i) सरकार की राजकोषीय क्षमता प्रभावित होती है
↳ राजस्व व्यय में वृद्धि पूंजी निवेश को प्रभावित करती है

(ii) निर्यात उद्योगों का आगत मूल्य बढ़ता है → जिससे WPI व CPI में वृद्धि होती है।

(iii) अत्यधिक महंगाई जनता की क्रय शक्ति को प्रभावित करता है

↓

कम प्रभावी मांग → कम उत्पादन

↓

कम सरकारी आय (tax)

↓

सरकार के खर्च करने की क्षमता प्रभावित → सामाजिक आर्थिक विकास ↓

उधारी व राजकोषीय घाटे में वृद्धि होती है

(सरकार का कुल ऋण 85.2% of GDP, FD → 6.2% of GDP)

(2) रुपये की परिवर्तनीयता प्रभावित

↓

रुपये के मूल्य में कमी → Forex प्रभावित

↓

RBI की मौद्रिक नीति में अनिश्चितता बढ़ती है

↓

महंगाई को नियंत्रित करने की क्षमता ↓

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

भारत द्वारा किए जा सकने वाले उपाय

① रणनीतिक रिजर्वों का निर्माण करना
→ भारत द्वारा लगभग 87 दिनों के लिए भंडारण किया गया है

② डिप्लोमेसी का उपयोग कर कम मूल्य में आयात सुनिश्चित करना
→ हाल ही में रूस-यूक्रेन संकट में रूस से कम मूल्य में तेल आयात

③ घरेलू उत्पादन में वृद्धि करना।

④ घरेलू क्षेत्रों में अन्वेषण व सर्वेक्षण कर नए क्षेत्रों का पता लगाना।

⑤ विदेशों में तेल क्षेत्रों में निवेश कर रणनीतिक परिसंपत्ति का अर्जन करना

⑥ रुपये में सौदों हेतु समझौता करना
- रूबल-रुपया समझौता उदाह।

विभिन्न उपायों द्वारा भारत कच्चे तेल की कीमतों के हानियों प्रभाव को कम कर सकता है मेथेनॉल अर्थव्यवस्था, आदि उपायों द्वारा पेट्रोलियम पर निर्भरता को कम करना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. The consistent high operating ratio of the Indian Railways is indicative of its incapability to generate high operational surplus. Explain the reasons behind this trend. Also, highlight the remedial measures taken by the government in this regard. (250 words) 15

भारतीय रेलवे का लगातार उच्च परिचालन अनुपात उच्च परिचालन अधिशेष सृजित करने में असमर्थता का संकेत है। इस प्रवृत्ति हेतु उत्तरदायी कारणों को स्पष्ट कीजिए। साथ ही, इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए उपचारात्मक उपायों को रेखांकित कीजिए।

भारतीय रेलवे का परिचालन अनुपात 0.95 ~ 0.97 है, जो रेलवे को अनुत्पादक परिवहन के रूप में स्थापित करता है।

इस प्रवृति के उतरदायी कारण।

→ रेलवे परिसंपत्ति का निम्नतर उपयोग।

↳ भारत में माल परिवहन हेतु रेलवे का केवल 27% उपयोग, जो कि सड़क परिवहन के 65% से कम है।

↳ खाली पड़े भूखंडों का अनुत्पादक उपयोग

→ क्रॉस सब्सिडाइजेशन

↳ भारतीय रेलवे विश्व में सबसे ज्यादा यात्रियों का परिवहन करती है, लेकिन किराया अर्जन

→ माल भाड़े व यात्रियों के लिए एक ही ट्रैक
  → इसलिए रेलवे के 60% ट्रैकों का उपयोग 100% से अधिक
  → माल भाड़े में 49% शेयर कोयला का

→ रेलवे प्रशासनिक व्यवस्था के विखण्डन व समन्वय का अभाव, रेलवे विकास प्राधिकरण का अभाव

→ सरकारी क्षेत्र की मोनोपॉली
  → इकोनॉमी ऑफ स्केल का अभाव
  → बारम्बार रेलवे के ठहराव के कारण परिवहन लागत ↑

→ रेलवे ट्रैकों का पुनरुद्धार धीमा
→ DFCs के निर्माण में देरी

सरकार द्वारा किए गए उपचारात्मक उपाय

① मिशन अवतरण → मानव संसाधन का सशक्तिकरण

② निजी क्षेत्र के लिए स्पेस → वंदे भारत ट्रेन आदि

③ DFCs का विकास

④ देबरॉय समिति की अनुशंसा पर IRMS का निर्माण

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(5) रेलवे क्रॉसिंग को ओवर ब्रिज या अंडर ब्रिज करना।

(6) NIP के माध्यम से रेलवे में पूंजीगत निवेश।

(7) भूमि मुद्रीकरण निगम व NMP द्वारा खाली पड़ी भूखंड का मुद्रीकरण

(8) अन्य उपाय
- स्टेशनों का आधुनिकीकरण
- रेलवे संरक्षा कोष का निर्माण
- रेलवे निर्माण को 7 km/day से 19 km/day करना
- रेलवे के मालगाड़ियों की गति 50 km/hr से 70 km/hr करना

NIP @75 Target

इस प्रकार सार्वजनिक परिवहन के रेलवे क्षेत्र के सुधारों का देश के आर्थिक - सामाजिक विकास पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. Micro food processing sector is the key driver of growth in the Indian economy as it encourages food processing innovation. In this context, state the challenges faced by the micro food processing sector and discuss how the recent initiatives taken by the government aim to address them.

(250 words) 15

सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक भारतीय अर्थव्यवस्था में संवृद्धि का प्रमुख चालक है क्योंकि यह खाद्य प्रसंस्करण नवाचार को प्रोत्साहित करता है। इस संदर्भ में, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों का उल्लेख कीजिए और चर्चा कीजिए कि किस प्रकार सरकार द्वारा हाल ही में प्रारंभ की गई पहलों का उद्देश्य इनका समाधान करना है।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र एक सनराइज उद्योग है जो 11% CAGR से वृद्धि कर रहा है।

→ सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक भारतीय अर्थव्यवस्था में संवृद्धि का चालक है

क्योंकि
- → क्षेत्रीय विषमता को कम करता है।
- → क्षेत्र विशिष्ट उत्पादों को प्रोत्साहित करता है।
- → कृषि अधिशेष की मूल्य वृद्धि में सहायक → उत्पादकों व उपभोक्ताओं को लाभ

सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र द्वारा की जाने वाली चुनौतियाँ

(1) अनौपचारिक क्षेत्र की प्रधानता।
↳ >90% इकाईयाँ अनौपचारिक

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(2) वित्त का अभाव

(3) तकनीक का निम्नस्तरीय अंगीकरण

(4) बैकवार्ड व फारवर्ड लिंक का अभाव

↓ - विखण्डित भू जोत अल्प कृषि अधिशेष को उत्पन्न करती है)

→ - बाजार तक पहुंच का अभाव

(5) बाजार आवश्यकता तक कम पहुंच

(6) खाद्य गुणवत्ता व परिक्षण (उदा. - ट्रेनिंग व्यवस्था, टेस्टिंग लैब) का अभाव

(7) प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी

सरकार द्वारा हाल ही में की गयी पहलें

(1) PM-FME (माइक्रो खाद्य उद्यम इकाईयों का औपचारिकरण)

→ इंटरेस्ट सब्वेंशन के साथ ब्याज की उपलब्धता

→ तकनीक का अंगीकरण

(2) FPOs को प्रोत्साहन → 10,000 FPOs के निर्माण द्वारा छोटे व सीमांत

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

किसानों के अधिशेष का संग्रहण

(3) कृषि अवसंरचना कोष (AIF) के माध्यम से कोल्ड स्टोरेज व PPCs की स्थापना करना

(4) PM-कृषि संपदा योजना द्वारा
- मानव संसाधन का विकास
- परिरक्षण अवसंरचना का विकास
- कोल्ड-स्टोरेज का निर्माण आदि

(5) एक जिला एक उत्पाद (ODOP)

(6) किसान रेल के माध्यम से नाशवान वस्तुओं की पहुंच में वृद्धि।

सरकार द्वारा विभिन्न उपायों द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि मूल्यवर्धित उत्पादों द्वारा उत्पादकों को अधिक मूल्य प्राप्त होने में सहायता मिल सके व उनकी 2022 तक आय दोगुनी हो सके।

14. Despite efforts by successive governments, equitable growth remains elusive and income inequality continues to persist in India. Discuss.

(250 words) 15

क्रमिक सरकारों के प्रयासों के बावजूद, न्यायसंगत विकास दुष्प्राप्य बना हुआ है और भारत में आय असमानता निरंतर बनी हुई है। चर्चा कीजिए।

विश्व असमानता रिपोर्ट - 2022 के अनुसार भारत के शीर्ष 1% लोगों की आय में 20% भागीदारी है।

सन् 1980 के बाद आय असमानता गुणांक (गिनी गुणांक) में भी वृद्धि हुई है जो दर्शाता है कि आय असमानता भी बढ़ी है।

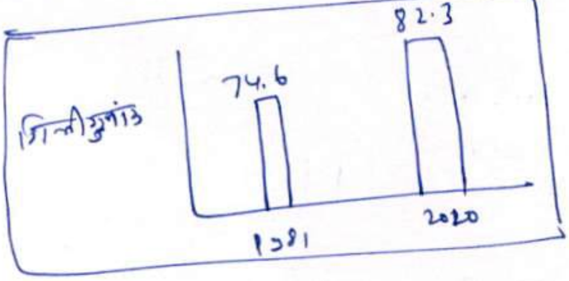

भारत में आय असमानता के कारण तथा न्यायसंगत विकास की कमी के कारण

(A) आय असमानता के कारण

① 82.17% कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है। (ES - 2021-22)

② श्रम गहन क्षेत्रों में तकनीकी उन्नयन का अभाव (जैसे वस्त्र व परिधान, जूते)

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(3) विनिर्माण क्षेत्र का विकास 1991 से ही 15-17% GDP पर स्थिर है।
→ (इससे अर्द्धकुशल व अकुशल श्रमिकों की नियुक्ति बाधित)

(4) कृषि क्षेत्र में श्रम बल 44% संलग्न है जबकि कृषि क्षेत्र की उत्पादकता न्यून है। (GDP में 15-20% योगदान)

(5) कौशल विकास का अभाव
(केवल 5.2% श्रमिक कौशलयुक्त है)

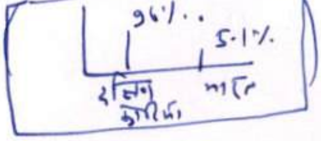

(6) भारत कौशल विकास रिपोर्ट के अनुसार — 46% शिक्षित कार्यबल नियोजन योग्य है (अर्थात शिक्षा रोजगार परक नहीं है)

(7) सामाजिक क्षेत्र — शिक्षा, स्वास्थ्य में सरकारी निवेश अति न्यून है।

न्यायसंगत विकास के अभाव का कारण

(1) वित्त का अभाव
↳ FDI का 78% केवल कर्नाटक, महाराष्ट्र व दिल्ली में संकेन्द्रित
↳ 44% केवल IT सेक्टर में

↳ बैंकों का NPA (PSBs का NPA 7.4%) (2022)

↳ ILFS संकट, TBS समस्या

(2) कौशल श्रमिकों की कमी।

(3) कठोर श्रम कानून

(4) EoDB के कोच बॉर्डर व्यापार व अनुबंधों के प्रवर्तन का अभाव

↳ FTAs का न्यायसंगत लाभ नहीं

↳ वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना के बाद भी इच्छित परिणाम नहीं

(5) अवसंरचना विकास का अभाव

(6) शोध के कम व्यय (0.65% of GDP)

↳ स्वदेशी तकनीक का अभाव

उपाय — (1) श्रम गहन उद्योगों को बढ़ावा (वस्त्र, चमड़ा आदि) (आर्थिक सर्वेक्षण)

(2) कौशल के माध्यम से उच्च आय वाले रोजगार सृजन

(3) SHGs, MFs आदि द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास

(4) FLPR को वर्तमान 25.1% से 30% तक बढ़ाना

(5) शिक्षा के निवेश 6% of GDP व स्वास्थ्य के 2.5% of GDP करना।

विभिन्न उपायों द्वारा SDG-10 को सार्थक बनाया जा सकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. Stating the factors that determine the employment situation of an economy in the long-term, discuss the measures that are needed for India to address its unemployment problem. (250 words) 15
किसी अर्थव्यवस्था की दीर्घावधि में रोजगार की स्थिति को निर्धारित करने वाले कारकों का उल्लेख करते हुए, उन उपायों की विवेचना कीजिए जो भारत में बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु आवश्यक हैं।

सेंटर फोर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के अनुसार भारत में बेरोजगार दर 6-8% है। नीति आयोग के अनुसार न केवल बेरोजगारी बल्कि अल्प रोजगार एक गंभीर चुनौती है।

दीर्घावधि में रोजगार की स्थिति को निर्धारित करने वाले कारक

1. कार्यबल का कौशल व तकनीक को अंगीकरण करने की दर
2. सरकारों की राजकोषीय क्षमता
3. अर्थव्यवस्था का औपचारीकरण → उत्पादकता में वृद्धि व उच्च आय वाले रोजगार सुनिश्चित करती है
4. रोजगारपरक शिक्षा व्यवस्था
5. स्वास्थ्य, शिक्षा व कौशल में सरकारी निवेश

(6) अनुसंधान व विकास को प्रोत्साहन देने की प्रवृति

(7) ग्लोबल सप्लाई चैन के साथ एकीकरण व विदेशी व्यापार

(8) ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

(9) संस्थानों की क्षमता (e.g. शहरी निकायों की क्षमता)

(10) अर्थव्यवस्था में मांग की प्रवृति

भारत में बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु उपाय

(1) पूंजीगत व्यय में वृद्धि करना
→ स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण

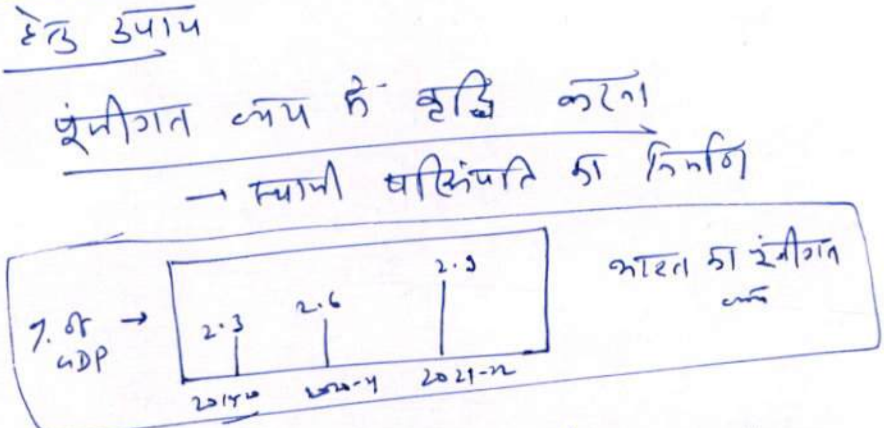

(2) कौशल विकास के माध्यम से युवाओं / जनांकिकीय लाभांश का लाभ उठाना
→ वर्तमान में 5.1% कार्यबल कुशल है जिसे 15% तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

(3) शिक्षा व उद्योगों का एकीकरण। (संलग्न)

(4) अनुसंधान व विकास पर GDP का 2% खर्च करना (NITI आयोग)
— वर्तमान में 0.65% of GDP है जिसमें निजी क्षेत्र <45% है।

(5) ईज ऑफ डूइंग बिजनेस — WB के अनुसार 10 पॉइंट की वृद्धि प्रति लाख 65 नई कंपनियाँ सृजन करती है।

(6) Startup को प्रोत्साहन

(7) ग्लोबल सप्लाई चेन से अंगीकरण

(8) AI, ब्लॉकचेन, ML, IoT आदि नवीन तकनीकों का अर्थव्यवस्था में समावेश करना।

उत्पादक व उच्च आय का रोजगार भविष्य के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करता है इसलिए उपरोक्त उपायों को शीघ्र अपनाना चाहिए व ताकि 2024 तक 5 tn $ की अर्थव्यवस्था का निर्माण हो सके।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

16. In view of the rapidly increasing socio-economic damage caused by disasters, integrating Disaster Risk Reduction (DRR) into development planning requires an effective stakeholder engagement mechanism. Discuss. **(250 words) 15**

आपदाओं के कारण तेजी से बढ़ रही सामाजिक-आर्थिक क्षति को देखते हुए, आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) को विकास योजनाओं में एकीकृत करने के लिए एक प्रभावी हितधारक जुड़ाव तंत्र की आवश्यकता है। विवेचना कीजिए।

जलवायु परिवर्तन जनित आपदाओं ने हाल में व्यापक सामाजिक-आर्थिक प्रभाव उत्पन्न किए हैं। ऐसे में आपदा प्रत्यास्थता हेतु प्रभावी हितधारक समन्वय आवश्यक है।

सेंडई फ्रेमवर्क ने विभिन्न प्रयासों द्वारा DRR को विकास योजनाओं में एकीकृत करने के लिए प्रभावी हितधारक जुड़ाव तंत्र की ~~चि~~ आवश्यकता को स्वीकार किया है।

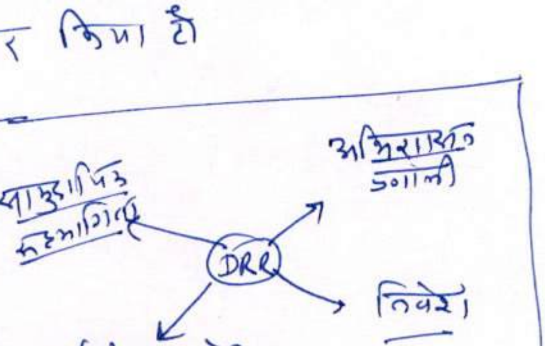

अंतर्राष्ट्रीय प्रयास

↳ भारत द्वारा CDRI के माध्यम से सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना।

↳ ग्लोबल प्लेटफॉर्म ऑन DRR के माध्यम से आपदा प्रबंधन को विकास योजनाओं में एकीकरण हेतु राष्ट्रों की सहायता।

राष्ट्रीय स्तर पर

↳ INCOIS द्वारा तटीय क्षेत्रों की सुभेद्यता का आकलन द्वारा मैप बनाना

↓

इससे विकास योजनाओं को उन क्षेत्रों की सुभेद्यता के अनुसार निर्मित करने में सहायता मिलेगी।

↳ विभिन्न संवेदन उपग्रहों द्वारा GLOFs प्रभावित क्षेत्रों में भू-उपयोग हेतु मार्गदर्शन

सामुदायिक स्तर पर

↳ राष्ट्रीय नीति के अनुसार आपदा के

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

BBB (बिल्ड बैक बेटर) सिद्धांतों को बिल्डिंग में शामिल करने हेतु प्रयासों का परामर्श लेना।

→ सामुदायिक परम्परागत ज्ञान को आधुनिक तकनीक से एकीकृत करना।

* 15 वें वित्त आयोग ने PRIs की क्षमता को विकसित करने का सुझाव दिया है ताकि प्रभावी आपदा जोखिम न्यूनीकरण को अपनाया जा सके।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. Provide an account of the existing carbon trading mechanisms in India. Also, discuss the significance of an efficient carbon trading market in the country and state the challenges that currently exist. **(250 words) 15**

भारत में मौजूदा कार्बन व्यापार तंत्र का विवरण प्रस्तुत कीजिए। साथ ही, देश में एक कुशल कार्बन व्यापार बाजार के महत्व पर चर्चा कीजिए और वर्तमान समय में विद्यमान चुनौतियों का उल्लेख कीजिए।

क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा पर्यावरणीय संधारणीयता को सुनिश्चित करने के लिए कार्बन व्यापार तंत्र की स्थापना की गयी थी।

भारत ने CDM (स्वच्छ विकास तंत्र) के कार्बन व्यापार तंत्र को प्रभावी रूप से स्वैच्छिक आधार पर अपनाया है।

इसके तहत

* अर्थव्यवस्था के 13 प्रमुख क्षेत्रों में PAT (परफॉर्म, अचीव व ट्रेड) प्रणाली का अंगीकरण
* नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में REC की व्यवस्था
* CERC द्वारा बाजार विनियमन

कुशल कार्बन व्यापार/बाजार का महत्व

① इससे भारत के INDC को पूरा करने में मदद मिलती है।

↳ भारत ने 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की गहनता को 45% of GDP कम करने का लक्ष्य रखा है।

↳ 2.5-3 bnt अतिरिक्त CO_2 का अवशोषण

② इससे ऊर्जा गहनता कम होगी → ऊर्जा संरक्षण

③ कम वायु प्रदूषण (भारत में प्रतिवर्ष 3% GDP की हानि)

④ प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण

⑤ उद्योगों के लिए प्रोत्साहन → उन्हें नवीन तकनीकों को अपनाने व अनुसंधान व विकास के लिए प्रेरित करता है।

⑥ नवीकरणीय क्षेत्र में रोजगार सृजन

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

वर्तमान समय के विद्यमान चुनौतियाँ

→ पेरिस समझौते के तहत SDM की अवधारणा ने पूर्ववर्ती CDM के व्यापार के बाधा उत्पन्न की है।

→ COP-26 ने CDM के तहत अर्जित प्रमाण पत्रों को 2030 तक विक्रय की अनुमति दी है।

→ तकनीकी परिवेश का अभाव
→ निजी क्षेत्र का कम निवेश

→ वित्त का अभाव

→ अनौपचारिक क्षेत्र की प्रधानता व MSMEs की पर्यावरणीय निवेश की कम क्षमता।

भारत अकेला G20 देश है जो अपने INDC को पूर्ण करने की ओर अग्रसर है। आधुनिक पर्यावरणीय तकनीकों के निवेश द्वारा कार्बन बाजार को और प्रभावी बनाया जा सकता है जिससे पर्यावरणीय संधारणीयता सुनिश्चित होगी।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. The menace of drug trafficking in India has been on a rise due to a mix of factors, both internal and external. Discuss. Also, state the challenges posed by drug trafficking to India's national security. **(250 words) 15**

भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग का खतरा आंतरिक और बाह्य दोनों कारकों के समन्वय के कारण बढ़ रहा है। चर्चा कीजिए। साथ ही, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष ड्रग ट्रैफिकिंग से उत्पन्न चुनौतियों का उल्लेख कीजिए।

भारत गोल्डन ट्रायंगल व गोल्डन क्रिसेंट के मध्य स्थित होने कारण ड्रग ट्रैफिकिंग का पारगमन मार्ग है। जिसमें आंतरिक कारक मिलकर वृद्धि करते है।

ड्रग ट्रैफिकिंग में आंतरिक कारकों की भूमिका

(1) NCRB के अनुसार पंजाब में 2020 में 38.5% मामले NDPSA के तहत दर्ज किए गये।

(2) असम राइफल्स ने मिजोरम में अनेक ड्रग कार्टेल को पकड़ा है
- उनके अनुसार गोल्डन ट्रायंगल अब गोल्डन पैंटागन बन गया है

(3) युवाओं की शहरीकरण के कारण तनाव वृद्धि

(4) बेरोजगारी की उच्च दर।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(5) एजेंसियों में तालमेल का अभाव

(6) तकनीकी आधुनिकीकरण की कमी प्रभावी निगरानी व कुप्रबंधन को प्रभावित करती है।

(7) उत्तरपूर्व में विभिन्न उग्रवादी समूहों की उपस्थिति।

· बाह्य कारकों की भूमिका

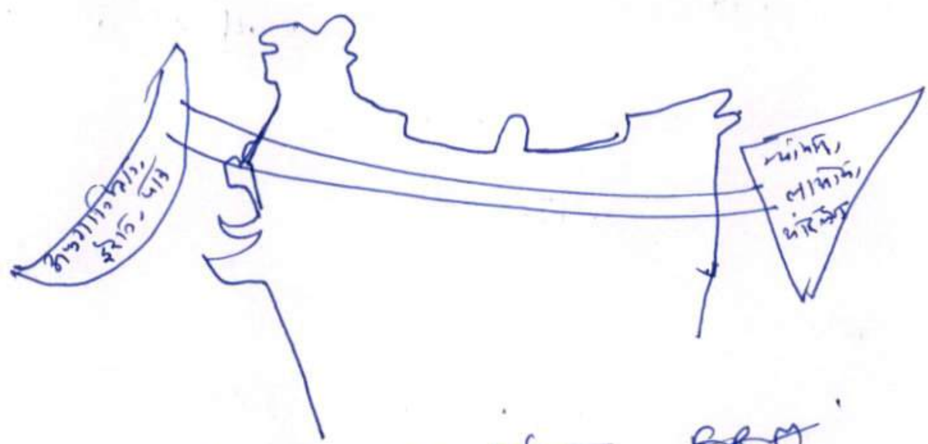

→ छिद्रिल सीमा (म्यांमार बॉर्डर पर ~~BRM~~ FMR की उपस्थिति)

→ अफगानिस्तान विश्व के 93% अफीम उत्पादक

→ पाकिस्तान की छद्म युद्ध की नीति

→ तटीय सीमा की असुरक्षा व बंदरगाहों पर निगरानी का अभाव (हाल के ही अफगानिस्तान के ड्रग को ~~...~~ रोप को अडानी पोर्ट पर)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां

- मादक पदार्थों के तस्करी व ड्रग ट्रैफिकिंग संगठित अपराध के रूप में आतंकवाद को वृहदरूप का निर्माण करती है।
- आंतरिक अशांति विद्रोही समूहों के सशक्तिकरण को प्रभावी बनाती है।
- वैध अर्थव्यवस्था और समक्ष खतरा
  - ↳ क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से अवैध ड्रग व्यापार (silkroad वेबसाइट) आदि
  - ↳ समानांतर अर्थव्यवस्था
  - ↳ मनी लॉन्ड्रिंग का कारण
- युवाओं के अपराधीकरण को प्रेरित करती है।

किए गए उपाय → NDPS अधि., 1985
- UNTOC कन्वेंशन का अंगीकरण आदि।
- ↳ NCB की स्थापना

NCB को अधिक सशक्त बनाकर व तकनीक के स्वीकरण तथा एजेंसियों के समन्वय के साथ सामाजिक-आर्थिक विकास द्वारा इस चुनौती से निपटा जा सकता है।

19. The Andaman and Nicobar islands' strategic significance in the Indian Ocean region (IOR) has been underplayed by India's policy of 'masterly inactivity and benign neglect'. Critically discuss. **(250 words) 15**

हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के रणनीतिक महत्व को भारत की 'कुशल अकर्मण्यता और सौम्य उपेक्षा' की नीति के तहत कम करके आंका गया है। समालोचनात्मक चर्चा कीजिए।

हिन्द महासागर क्षेत्र में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह भारत की रणनीतिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण आधार है।

अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह के रणनीतिक महत्व को 'कुशल अकर्मण्यता और सौम्य उपेक्षा' की नीति के तहत कम आंकने का प्रभाव -

→ भारत की छवि अन्य आक्रमक की जगह शांति स्थापक की (इसलिए भारत ने कुशल अकर्मण्यता की नीति अपनायी)

→ व्यापारिक हितों का बढ़ावा देना। यह क्षेत्र महत्वपूर्ण मलक्का जलसंधि के पास स्थित है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

→ 'सौम्य अपेक्षा की नीति' ने बंगाल की खाड़ी व अंडमान सागर को विवादों से मुक्त रखा।

↳ इनके इंडोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया व सिंगापुर के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुई।

→ आपदा राहत अभियानों में भूमिका आदि।

नकारात्मक प्रभाव

① चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' की नीति के कारण
→ निकट स्थित म्यांमार के बीच पर चीन की सैन्य उपस्थिति भारत की इस क्षेत्र में 'नेट सुरक्षा प्रदाता' की छवि को नुकसान पहुंचा रही है।

② अंडमान व निकोबार द्वीप के निर्जन द्वीपों का उपयोग तस्करी डकैती, ड्रग्स कार्टेल्स द्वारा उपयोग

③ इस क्षेत्र की उपेक्षा ने सैन्य प्रतिष्ठानों की स्थापना व सैन्य प्रयासों को धीमा किया

(4) इससे ALN का सामाजिक - आर्थिक विकास (जैसे - शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, अवसंरचना विकास आदि) अल्प हुआ है।

भारत द्वारा इस क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास

→ वर्तमान में ALN द्वीप समूहों का विकास करने के लिए 'द्वीप विकास' समिति ने रूपरेखा तैयार की है
   ↳ ALN में आर्थिक विकास -
   ↳ जापान के साथ भागीदारी में विकास
   ↳ शिप निर्माण उद्योग
   ↳ केबल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास

→ भारत की त्रिसेवा कमांड की स्थापना

भारत को ALN द्वीपों को उसके सामरिक महत्व के अनुसार विकसित करना चाहिए ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ - साथ इस क्षेत्र में खुले व मुक्त ऑर्डर को बनाए रखा जा सके।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. India has recently commissioned the world's first large International Liquid-Mirror Telescope (ILMT). How will the newly commissioned telescope aid in India's astronomical observations and research? **(250 words) 15**

हाल ही में, भारत ने विश्व का पहला विशाल इंटरनेशनल लिक्विड-मिरर टेलीस्कोप (ILMT) स्थापित किया है। यह नवनिर्मित टेलीस्कोप खगोलीय पर्यवेक्षणों और अनुसंधान में भारत की किस प्रकार सहायता करेगा?

भारत ने विश्व का पहला विशाल इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया है।

यह टेलीस्कोप भारत की निम्न प्रकार सहायता करेगा।

→ देश के वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा।

→ खगोल विज्ञान में भारतीय विशेषज्ञता का प्रसार

→ विभिन्न आंकड़ों की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि

→ ISRO के अभियानों के साथ अभियान